श्री लक्ष्मण सिंह: चैयरमेन साहब, आजादी से पहले हिन्दुस्तान की फौज का सिक्का सारी दुनिया में जमा हुआ था और सारे डरते थे।

श्री संघ प्रिय गौतम: आज भी डरते हैं।

श्री लक्षमन सिंह: मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। I do not interfere in anybody's speech. अभी मंत्री जी ने कहा कि भर्ती आबादी के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब, हिरयाणा और हिमाचल जिन्होंने आबादी को कंट्रोल किया और यू. पी. बिहार जिन्होंने नही किया तो क्या उन को यह सजा है? यहां भी रिजर्वेशन की बीत आ गयी है? मैं अर्ज करना चाहूंगा मंत्री जी से कि फौज देश की रक्षा करती है और सभी कुछ फौज के ऊपर दारोमदार है। आप की बॉर्डर पर चारों तरफ एनेमीज बैठे हैं। इतना अंधकार मचा हुआ है औ चारों तरफ मिलिटेंसी है। तो क्या आप यह गौर करना चाहंगे कि बजाए आबादी के लिहाज से मेरिट के हिसाब से भर्ती हो? कम से कम फौज को तो बख्श दीजिए इस रिजर्वेशन से। यहां तो ऐसा काम न कीजिए आप वरना यह जो आप का बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है और हिंदुस्तान की आबादी वन थाउजेंड मिलियन हो चुकी है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? इसी तरह से जब भी एसेंब्लीज और पार्लियेमेंट में रिजर्वेशन की बात आएगी तो आप आबादी को लेकर बैठ जाएंगे जिस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल स्टेट्स तो मारे जाएंगे जोकि आबादी को कंट्रोल करते हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप इस आबादी के नॉर्म को बदलिए जोकि आबादी तो आप को खाए जा रही है और इसी कारण आप के 50 परसेंट लोग बिलों पावर्टी लाइन हैं आप चाइना को देखिए, वहां जीरो परसेंट पॉपुलेशन हो चुकी है। तो क्या मंत्री जी हाउस को यह यकीन दिलाएंगे कि आबादी का नॉर्म छोड़कर भर्ती प्योरली मेरिट पर आ जाए? फिर इस में जो ताकतवर होगा, वह जाएगा। चैयरमेन साहब, यही सवाल मैं मंत्री जी से आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरिट के बगैर भर्ती होती ही नहीं है।

श्री लक्षमन सिंह: अभी तो आप ने कहा कि पॉपुलेशन के बेसिस पर है।

श्री सभापति: आप ने सुनी नहीं, जो बात कही उन्होंने।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अब रहा सवाल कि किसी के साथ क्या अन्याय हो रहा है विशेषकर पंजाब के संदर्भ में क्योंकि माननीय सदस्य का लक्ष्य मुझे वहीं नजर आया। ...(**व्यवधान**)...

सभापति जी, हम नहीं चाहते थे कि यह बहस इस तरह से चले क्योंकि यह ठीक नहीं है। हम देश को सेना की समस्याओं की चर्चा करते हैं तो वह एक प्रदेश की नही होतीं, समूचे देश में वही समस्याएं हैं, कहीं कुछ होती है और कहीं कुछ होती हैं। सभापति जी, मैं ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा। केवल एक ही उदाहरण दूंगा। जहां तक रेशियो ऑफ पॉपुलेशन की बात है, पंजाब का मैंने बताया 2.4 और पत्तर प्रदेश का 16 आता है। आज जिस रेशियों पर पंजाब में फर्ती हो रही है, उसी रेशियो को अगर उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहेंगे तो मैं एक साल का उदाहरण देता हूं। जो मैंने अभी आंकड़े पढ़े थे, उत्तर प्रदेश एक नम्बर पर और पंजाब दो नंबर पर है और अगर मैं उस आधार पर चलूं तो उत्तर प्रदेश में उस साल जो भर्ती हुई थी, और उसमें और अधिक लगभग 20 हजार की भर्ती होनी चाहिए थी। जो आप ने शिकायत की है ...(**व्यवधान**)...उस शिकायत के आधार पर कोई करने नहीं जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री लक्षमन सिंह: यह ताकत का मामला है, उसमें तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को ही मिलेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस सवाल को हम प्रदेश प्रदेश के मामले के तौर पर न देखें। मेरिट के बगैर सेना में कोई नहीं जाएगा और जिन प्रदेशों में और भी कोई संभावनाएं है तो उन संभावनाओं के हम पूरा करते रहेंगे।

श्री सभापित: क्यूश्चन नंबर 403.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: सर, एक क्युश्चन। जो असल क्यूश्चन था वह तो किसी ने उठाया ही नहीं।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं। आधा घंटा हो गया इस सवाल पर। क्युशचन नंबर 403.

Representation to Minorities in Para-Military and Police Forces

*403. SHRI K. RAHMAK KHAN: Will the Minister of HOME AFPAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are committed to provide adequate representation to minorities in para-military and police forces;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard during last three years; and

(c) the percentage of different minorities recognised by National Minorities Commission in para-military forces and central forces, force-wise?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) With a view to providing adequate representation to all regions and communities in Central Para Military Forces, recruitment is carried out in different parts of the country after due publicity. Special efforts are also made to ensure that eligible candidates from minority communities are made aware of the employment opportunities and recruitments in the Central Para Military Forces.

(c) The percentage of representation of minorities in the CPMFs is given below:

	Muslim	Christian	Sikh	Budhist/ Zorastrians	Total
BSF	4.82	2.02	3.64	0.15	10.63
CRPF	5.80	2.47	3.30	0.68	12.25
ITBP	2.50	1.15	3.98	1.24	8.87
CISF	3.35	3.00	5.00	0.52	11.87
Assam Rifles	2.72	7.50	0.77	0.62	11.61

SHRI K. RAHMAN KHAN: Mr. Chairman, Sir, the Government, in order to provide social justice to minorities, have issued directives, which are popularly known as the 15-point Programme. One of the directives is to give adequate representation in police forces to the minorities. Further, the National Integration Council has also recommended that there should be a mixed police force. My question is whether the Government is committed to provide adequate representation to minorities in para-military and police forces. The answer which is given is, "Special efforts are also made to ensure that eligible candidates from minority communities are made aware..." So, the answer is not very clear. I would like to know from the hon. Minister as to what steps are being taken to see that there is adequate representation to minorities in para-military and police forces. Awareness is there, but how do they ensure the adequate representation.

श्री लाल कृष्ण आडवाडी: सभापति जी, एक दृष्टि से अच्छा ही है कि पूर्व का सवाल और यह सवाल दोनों एक साथ आए हैं क्योंकि पूर्व के सवाल में बल इस बात पर था कि मेरिट की चिंता न करते हुए सब देश के सभी प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एप्रोच अपनाई जा रही है रिक्रूटमेंट में और इसमें इसके विपरीत आग्रह किया जा रहा है कि मेरिट को डिसरिगार्ड करते हुए कुछ करना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई सरकार ...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद आजम खान: नहीं, ऐसा नहीं कहा। ...(**व्यवधान**)...

†[**شری محمداعظم خان**: نہیں ایسا نہیں کہا۔۔۔"مداخلت"۔۔۔]

श्री के. रहमान खान: यह गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई नहीं कहा, मेरिट के बगैर. यह कोई नही कहा।....(**व्यवधान**)....

श्री सभीपति: आपकी बात सुन ली। आप बैठिए।

SHRI L.K. ADVANI: I will answer your question and you will be satisfied. In the first sentence, I have said, with a view to provide adequate representation to all regions and communities in Central Paramilitary Forces, recruitment is carried out in different parts of the country after due publicity. Now, adequate rep-

†[ ]Transilteration in Arabic Script

resentation is still there and this is what was referred to. But, in order to achieve adequacy, the Government cannot disregard merit. This is what I am saying. Therefore, the Government is seeing to it that all sections arc apprised of it. For example, in case of the minorities, we take special efforts to see that whenever there is recruitment, wide publicity is given through the electronic media in those sections. The Minorities Commission, both at the national level and the State level are informed about it. Apart from that, the district administration develops liaison with the minority communities, so that for recruitment they can come in. Also, we see to it that in the Recruitment Boards, members of the minority community are there. This is the manner in which the Government tries to see that there is adequate representation in the para-military forces for the minorities also. Though consistently from day one, it has been the policy of the Government, irrespective of who comprises the Government, that there should be no reservation on the basis of community or religion.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, this is my second supplementary question. The hon. Minister has said that adequate awareness is created through electronic media or through other things. I respectfully submit that there is absolutely no publicity, no awareness. As a Member of Parliament, I have never heard of any such electronic media or other things being used. This is the impression that I have. The second part of the question is regarding the population of the Muslims. I had asked for different categories of minorities. It is 12 per cent in the country as far as the census is concerned. Among all the forces, CRPF' has the highest representation of 5 per cent and for the rest it is less. So, I would like to know from the hon. Minister whether in the interest of social justice this representation—I am stressing, in the interest of social justice—is adequate. I would like to know whether the Central Government will instruct the State Government to see that social justice is provided and adequate representation is given to the different sections. I am stressing National integration Council to see that the police force is not partial. They have recommended after due deliberation that there should be a mixed force in this country.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पचास साल में क्यों नहीं किया? ....(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: सत्रह परसेंट पापुलेशन शेडयूल्ड कास्ट की है और एक परसेंट भी इसमें नहीं है. ....(**व्यवधान**)...

श्री के. रहमान खान: वह बाद में आप जरूर पूछिए।....(**व्यवधान**)...

SHRI L.K. ADVANI: I may inform the House that the minority educational institutions, organisations, Anglo-Indian institutions and the local Employment Exchanges are also informed whenever recruitment to these Central Paramilitary forces takes place, so that adequate awareness is created among them. Today, the Minorities Commission recognises five communities as minorities. These five are: Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Zoroastrian. It happeijis that excepting the Muslim community, the rest of the minority communities have more representation than the percentage of their population. Among the minority communities, it is only in the case of the Muslim community, the percentage is less. I would plead with the leaders of the Muslim community to ensure that more and more people get recruited to the Central paramilitary forces. There would be no objection to that. But the point is, awareness has to be there. I may mention here that in many States, the representation is not adequate. Mention was made by the hon. Member here about the Scheduled Castes. Sir, I happen to belong to Gujarat. I find that Gujarat is very inadequately represented. This is because there is not that tendency to get into the Central paramilitary forces. For that, the paramilitary forces or the Government cannot be blamed. It is really the community itself which has to come forward.

श्री मोहम्मद आजम खान: यह बात नहीं है जैसा गृह मंत्री जी ने शुरू में कहा कि मेरिट को बिल्कुल बाला-ए-ताक रखकर कोई फैसला पैरा मिलिट्री फोर्सिस में किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी अमली दुश्वारियां हैं, जिनकी बिना पर माइनॉरिटी के लोगों तक इत्तिला ही नहीं पहुंच पाती। अभी मुसलमानों के बात भी कही गई, सिखों का इससे पहले सवाल आया था, अब जो अमली दुश्वारियां हैं वे हैं अवेयरनैंस की। जैसे आप कहते हैं कि आपने इत्तला पहुंचा दी, लेकिन वाक्या ह है कि इत्तिला नही पहुंच पाती। मिसाल के तौर पर वे अखबारात में इश्तहार नहीं जाता। उसके अलावा, सभापति महोदय, एक और बड़ी परेशानी यह है कि जब रिक्रूमेंट होता है और आफिसर्स बैठे होते हैं, यह सैंट्रल गवर्मेंट के आदेश भी हैं और स्टेट गवर्मेंट के भी हैं कि उनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी एक अधिकारी होना चाहिए, मैं सदन से भी कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं कि सारे अफसर आई. पी. एस. रैंक के बैठे होंगे, डी. आई. जी. आई. जी. बैठे होंगे, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रजेंटेटिव सी. ओ. के लैवल का होगा। तो जब रिक्रूटमेंट की आखिरी मंजिल होगी तो उस वक्त क्या सी. ओ. लैवल का अधिकारी आई. पी. एस. या सीनियर आफिशियल्स के मुकाबले अपनी राय का इजहार करने की हिम्मत रखेगा? ऐसा 99 प्रतिशत होता है। तो क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा और यकीन दहानी कराई जाएगी कि इस तरह की भर्ती में, जो पैरा मिलिट्री फोर्सिस की बात कही गई है, माईनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारी का लैबल भी बाकी अधिकारियों के बराबर होगा? नाइंसाफी होने की वजह यही है कि उस लैवल पर, जहां भर्ती हो रही है, वहां भी वही जहनियत काम करती है। हम अपनी बात शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां शक और शुबहे की सुई जाकर कहीं रुकती है। लिहाजा मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर भर्ती के वक्त गलत अधिकारी को वहां बैठाकर जो नाइंसाफी होती है, क्या उस विषमता को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार कोई निर्देश यग आदेश जारी करेगी?

شری محمداعظم خان:یہ بات نہیں ہے،جیسا گرہ منتری جی نے شروع میں کہا کہ میرٹ کوبالکل بالائے طاق رکھکر کوئی فیصلہ پیراملٹری فورس میں بات بھی کہی گئی، سکھوں کااس سے پہلے سوال آیا تھا،اب جوعملی دشواریاں ہیں وہ ہیں او پرنہیں کی۔جیسے آپ کہتے کیاجاتا ہے،لیکن کچھ ایسی عملی دشواریاں ہیں،جن کی بناپرمائنارٹی کے لوگونتک اطلاع ہی نہیں پہنچ پاتی۔ابھی مسلمانوں کی ہیں کہ آپ نے اطلاع پہنچادی،لیکن واقعہ یہ ہے کہ اطلاع نہیں پہنچ پاتی۔مثال کے طور پروہ اخبارات جومسلم کمیونٹی میں پڑھے جاتے ہیں،ان اخبارات میں اشتہارات نہیں جاتا۔اسکے علاوہ،سبھاپتی مہودے ایک اوربڑی پریشانی یہ ہے کہ جب ریکروٹمنٹ ہوتا ہے اورآفیسرزبیٹھے ہوتے ہیں، یہ سینٹرل گورنمنٹ کے آدیش بھی ہیں اوراسٹیٹ گورنمنٹ کے بھی ہیں کہ ان میں مائنارٹی کمیونٹی کا بھی ایک ادھیکارہونا چاہئے،میں سدن سے بھی کہنا چاہتا ہوں اورآپ کے مادھیم سے سرکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے افسرآئی۔پی۔ایس رینک کے بیٹھے ہونگے،ڈی۔آئی۔جی۔،آئی۔جی۔بیٹھے ہونگے،لیکن مائنارٹی کمیونٹی کارپیرزنٹیٹیو سی۔او۔کے لیول کا ہوگا۔توجب ریکروٹمنٹ کی

†[]Transilteration in Arabic Script

آخری منزل ہوگی تواس وقت کیا سی-ار-لیول کا ادھیکاری آئی-پی-ایس یا سینئرآفیشیل کے مقابلے اپنی رائے کااظہار کرنے کی ہمت رکھے گا؟ایسا ۹۹فیصدہوتا ہے۔ توکیا اس بات کوسنشچت کیا جائے گا اوریقین دھانی کرائی جائے گی کہ اس طرح کی بھرتی میں'جوپیرا ملٹری فو رسیزکی بات کہی ہے'مائنارٹی کمیونٹی کے ادھیکار کا لیول بھی باقی ادھیکاریوں کے برابر ہوگا؟ناانصافی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس لیول پرجہاں پربھرتی ہورہی ہے'وہاں بھی وہی ذہنیت کام کرتی ہے۔ہم اپنی بات کی شروعات وہاں سے کرتے ہیں'جہاں شک اورشبہ کی سوئی جاکرکہیں رکتی ہے۔لہذا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں پربھرتی کے وقت غلط ادھیکاری کووہاں بٹھا کرجوناانصافی ہوتی ہے' کےا اس وشمتاکودورکرنے کے لئے کیندرسرکارکوئی نردیش یاآدیش جاری کرےگی؟}

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कहीं पर भी नाइन्साफी होती है तो उसको दूर करने का प्रयत्न सरकार करेगी। मैं यह भी कह सकता हूं कि कुछ पैरा मिलिट्री फोर्सिस के ऐसे सैक्शन हैं जहां मुस्लिम रिप्रजेंटेशन उनके पापूलेशन रेश्यो से ज्यादा है. जैसे आर. ए. एफ. है रेपिड एक्शन फोर्स है, उसमें Muslim representation is around 20 per cent against their population ratio of 17 per cent. तो ऐसी भी कुछ फोर्सिस है जहां पर the percentage of Muslim representation on the whole may be less, but, in some sections, it is even more than the population.

मोहम्मद आजम खान: मेरा प्रश्न यह नहीं था, मेरा प्रश्न यह था कि रिक्रूटमेंट के वक्त जो आखिरी मंजिल है, जहां चार अधिकारी बिठाए जाते है और तथा माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी एक अधिकारी होता है तथा उसका लैवल बहुत नीचे का होता है, तो क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी के उस अधिकारी का भी लैवल वही होगा जो बाकी अधिकारियों का होगा?

}**شری محمداعظم خاں**: میرا سوال یہ نہیں تھا'میرا سوال تھاکہ ریکرونمنٹ کے وقت جوآخری منزل ہے' جہاں چار ادھیکاری بٹھائے جاتے ہیں اوروہاں مائنارٹی کمیونٹی کا بھی ایک ادھیکاری ہوتا ہے اوراس کا لیول بہت نیچاہوتا ہے 'توکیامائنارٹی کمیونٹی کے اس ادھیکاری کا بھی لیول وہی ہوگا جوباقی ادھیکاریوں کا ہوگا؟}

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सदस्य ध्यान में लाएंगे तो मैं जरूर देखूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खान: स्पेसिफिक केस का सवाल नहीं था।

}**شری محمداعظم خاں**:اسپسنک کیس کاسوال نہیں تھا۔}

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं सदन को आश्वास्त करना चाहूंगा कि कहीं पर नाइंसाफी नहीं होगी।

†[ ]Transilteration in Arabic Script

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister has very correctly pointed out that the Rapid Action Force contains a larger percentage of persons belonging to the minority communities and that is why the effectiveness of the Rapid Action Force in controlling communal riots and other types of sensitive situations is much more, compared to the ordinary police forces.

The higher percentage which he has referred to has taken place because of some deliberate actions taken by the administration to ensure that there was a larger percentage. The hon. Minister has given in his statement the percentages in regard to the CRPF and the BSF. These are the two most important Central paramilitary Forces which are being deployed by the State Governments whose dependence and reliance on them is increasing. It has been mentioned in the statement that some special efforts will be made. Particularly in the context of the percentages which he has given in regard to the CRPF and the BSF, I want to know whether the efforts that were made in the case of the Rapid Action Force will be made in the case of the CRPF and the BSF also.

SHRI L.K. ADVANI: The composition of these para-military forces, as it is today, is the outcome of the policies pursued over the years, for so many years. There is no intention of changing any of those policies. Nevertheless, if the composition has remained what it is, it should be appreciated that it is because we would like to see no shortfall in the efficiency, efficacy of the Forces. Only in Order to see that a completely adequate representation is given to all sections, there is no intention of changing any of those policies. I am sure that everyone would appreciate this.

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन, हमें आपका संरक्षण चाहिए....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: किस बात के लिए?

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, श्री आजम खान साहब ने स्पष्ट एक प्रश्न किया है कि....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: वह हो गया।

श्री रमा शंकर कौशिक: उसका जवाब नहीं आया है। उसका जवाब आप दिलाएंगे। आप हमारे संरक्षक हैं।....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: उन्होंने जवाब दे दिया है....(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक: आपको हमें संरक्षण देना चाहिए....(**व्यवधान**)... जवाब तो आना चाहिए....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: उन्होंने कहा है कोई स्पैसिफिक केस आप लाएं हमारे पास।

श्री रमा शंकर कौशिक: यह नहीं कहा है, श्रीमन ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: कहा है उन्होंने स्पैसिफिक केस का कहा है उन्होंने....(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर दीक्षित: स्पैसिफिक केस का सवाल नहीं है श्रीमन। जो बोर्ड बैठता है, उस बोर्ड में जो माइनॉरिटी का आदमी बैठता है, वह लोअर लेबल का बैठता है। अगर वह यह कह दें कि अगर ऐसा है तो में उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करूंगा तो भी बात बन जाती। हमें संरक्षण चाहिये, हमें अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहिए। सभापति जी, आप हमारे संरक्षक हैं, संरक्षा करिए। चूकि स्पष्ट प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर भी स्पष्ट आना चाहिए।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, representing, as I do, a Muslim-majority State in this House, I would certainly welcome an increase in the representation of Muslims. I have one question that arises from the reply given by the hon. Home Minister. He has said that the National Minorities Commission has recognised five minorities—Muslims, Oiristians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians. There are at least six States in India, where Hindus are in a minority-^Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Nagaland, Mizoram and Lakshadweep. May I ask of the Home Minister whether in those States where Hindus are in a minority, will they also receive

the protection at the State level of the National Minorities Commission?

SHRI L.K. ADVANI: Sir, this supplementary does not directly relate to the Home Ministry. But, I will say that this is not a question but a suggestion for action.

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, I want to know from the hon. Home Minister whether the Government's policy is to recruit people on the basis of religion, whether there are policies under which some people are consciously kept away and whether there is any discriminatory attitude by which some persons are kept away.

SHRI L.K. ADVANI: There is no discrimination against anybody. No favouritism is shown to any community. This is the policy of the Government.

SHRI M.P.A. SAMAD SAMADANI: One major aspect of the main question is yet to be answered by the hon. Minister. The main question has an important part. That is about the recommendation of the National Integration Council.

This recommendation of the National Integration Council cannot be ignored by just stating that we are not for reservation and that we are not for recruitment. The National Integration Council is a very responsible body. It has, in its past record, great deliberations and recommendations regarding the unity of the nation. I think, there are cultural...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Bidding Exemption to Hydcl Projects

*404. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that new hydel projects will be exempted from competitive bidding; and

(b) whether this will apply to all hydel projects?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) Power generation projects with an estimated cost exceeding Rs. 100 crores and promoted through the private sector after 18.2.1995 are required to follow the competitive bidding process. Competitive bidding is not mandatory for projects meant purely for captive use and for expansion projects. This policy applies to hydel projects also.

Ali Sena

*405. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the existence of Ali Sena as reported in 'The Pioneer', dated the 10th June, 1998;

(b) what are the aims and objects of Ali Sena; and

(c) whether Ali Sena is confined to a particular community/section, and if so, which ones?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes Sir.

(b) and (c) Ali Sena (Full name Rash-triya Ali Sena) was reportedly floated in early part of 1996 to gain popularity among Muslims in view of the elections to the Municipal Corporation of Delhi.

Construction of Water Canal

*406. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: WilLthe Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to construct a water canal on the Kutch border of India as a defence measure between India and Pakistan;

(b) when was it proposed by the defence authorities;

(c) whether Government are willing to consider the proposal or not;